may affect the overall growth rate in agriculture in the current year which is likely to be lower than that observed in 1994-95.

(d) The Government is revising upward the minimum support prices paid to the farmers for their agricultural commodities.

(e) At present, there is no restriction on the interestate movement of wheat and levy-free rice throughout the country. To remove export restrictions and bring domestic procurement prices at par with international prices, the export of basmati and non-basmati rice is allowed freely without any quantitative or Minimum Export Price Restriction. Export of wheat products and hybrid jowar is under open General Licence (OGL)

Vocational Training Centres for SCs/STs in Gujarat

2020. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the names of the places in Gujarat especially in the Kutch-Saurashtra region, where vocational training centres are proposed to be set up for the educated unemployed youth belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) the time by when the training related facilities will be provided in these centres; and

(c) the amount sanctioned for each of the aforesaid centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K.V. THANGKA BALU): (a) The place-wise and district-wise details of the Vocational Training Centres for tribal youth are given below:—

1. Ankalach	Valsad
2. Chhotaudepur	Vadodara
3. Rajipila	Bharuch
4. Mandvi	Surat
5. Danta	Palanapur
6. Dahod	Panchmahal
7. Kaparade	Valsad

There is another scheme namely 'Aid to Voluntary Organisations for the Welfare of SCs' under which grant-in-aid is given to Voluntary Organisations for setting up various vocational training centres for the educated unemployed youth belonging to SCs. So far, no project under the scheme has been sanctioned in Gujarat.

(b) The aforesaid Centres except the Centres at Ankalach and Chhotaudepur are yet to become operational as per latest progress report received from the State of Gujarat Land has been allocated in Kaparada. In other cases efforts are made to get land.

(c) A total amount of Rs. 103.46 lakhs has been released for setting up of 7 Vocational Training Centres in the State of Gujarat so far. The amount for each Centre has been sanctioned @ Rs. 14.78 lakhs.

पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण

2021. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत ग्रामसभा जमुवांवा में भी पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मंजूरी कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद

नेताम): (क) जी हां। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुक्कुट परिसरों के निर्माण करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में आजमगढ़ जिला शामिल है। तथापि, अन्तिम रूप से स्थान तय करने का कार्य राज्य सरकार का है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की इसी वित्तीय वर्ष में ही मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है।

फूलों का उत्पादन

2022. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में फूलों का उत्पादन होता है;

(ख) वर्तमान में जिन फूलों का उत्पादन किया जा रहा है, उनके नाम तथा प्रमुख किस्में क्या-क्या हैं;

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में फूलों का उत्पादन हुआ;

(घ) पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई और वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) अलग-अलग फूलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के क्रमबद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, मोटे तौर पर उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में 1992-93 के दौरान 2.06 लाख मी॰ टन पारम्परिक फूलों तथा 45.42 करोड़ "कट" फूलों का उत्पादन किया गया था।

(ख) परम्परागत फूलों के अंतर्गत उगाये जाने वाले प्रमुख फूल हैं—गुलाब (देसी), गेंदा, चमेली, गुलवापदी क्रासदरा और एस्टर जबकि कट मूल है—गुलाब, ग्लेडिओल्स, कार्नेशन, टयूबरोस तथा आरचिड्स।

(ग) 1993-94 और 1994-95 के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) पुष्पोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1994-95 में राज्यों को कुल 148.75 लाख रुपये दिये गये थे और 1995-96 के लिए 200 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। राज्यवार जारी की गई और आवंटित धनराशि विवरण I में दी गई है। **(नीचे देखिए)** इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने "कट" फूलों के उत्पादन के लिए 1994-95 के दौरान लाभानुभोगियों को साफ्टलोन के रूप में 11.62 करोड़ रुपये सीधे ही दे दिये हैं।

(ङ) से (च) सरकार ने निर्यात के विकास एवं संवर्धन के लिए पुष्पोत्पादन की पहचान अत्यधिक फोकस वाले क्षेत्र के रूप में की है। फूलों के निर्यात को सरल बनाने संबंधी नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राज्यवार निर्गमित तथा आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना का परिव्यय	निर्गमित राशि 1994-95	आबंटन 1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.00	1.50	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	0.50	0.50